सुविचार

खुद का अपमान कराके जीने से तो अच्छा मर जाना है क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन दु:ख होता है।

-चाणक्य

RNI No. RAJHIN/2001/05699

जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का एकमात्र समाचार-पत्र

www.hellosarkar.com www.hellosarkar.com www.hellosarkar.com www.hellosarkar.com www.hellosarkar.com

हैलो सरकार

पल-पल की टी.वी. एवं रेडियो खबरों के लिए लॉग ऑन करें- www.hellosarkar.com

हैलो सरकार समाचार पत्र में नियमित पाठक बनने, समाचार की प्रति मंगवाने व विज्ञापन देने हेतु सम्पर्क करें

फोन: 0141-2202717

मो: 9214203182

वाट्सप नं. 9928078717

वर्ष-25 | अंक-258 | दैनिक प्रभात संस्करण | जयपुर, शुक्रवार 22 मई, 2026 | पृष्ठ-4 | मूल्य: 2.50

मंत्री 2047 के विजन पर करें काम, फाइलों में न हो देरी-मोदी

हैलो सरकार न्यूज, नई दिल्ली। सेवा तीर्थ में आयोजित केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद की अहम बैठक करीब साढ़े चार घंटे के लंबे मंथन के बाद संपन्न हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस मैराथन बैठक में सरकार के आगामी एजेंडे, प्रमुख ढांचागत सुधारों (ऋद्ध-द्धश्हृद्ध्र) और भविष्य के रोडमैप पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को %विकसित भारत 2047% के संकल्प को पूरा करने के लिए जी-जान से जुटने का स्पष्ट संदेश दिया। जो हो गया उसे छोड़िए, भविष्य पर फोकस कीजिए - क्रू मोदी सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को नसीहत देते हुए कहा कि विकसित भारत 2047 केवल एक नारा नहीं, बल्कि सरकार की अटूट प्रतिबद्धता है। सभी मंत्रालय अपनी योजनाओं को इसी दीर्घकालिक विजन के अनुरूप तैयार करें। कड़ा रुख अपनाते हुए पीएम ने कहा, जो हो गया, उसे पीछे छोड़िए, अब केवल और केवल भविष्य पर फोकस कीजिए।

फाइलों की लेत-लतीफी पर सख्त निर्देश, जयशंकर ने दी ब्रीफिंग

बैठक में प्रशासनिक स्तर पर ढिलाई को लेकर प्रधानमंत्री ने सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंत्रालयों में फाइलें तेजी से निपटनी चाहिए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी या नौकरशाही की अड़चन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्रियों को उपलब्ध समय में अधिकतम उत्पादकता हासिल करने को कहा गया है।

इसी बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री की हालिया 5 देशों की यात्रा के रणनीतिक महत्व और राजनयिक उपलब्धियों को लेकर विस्तार से ब्रीफिंग दी।

कम दखल, ज्यादा मदद और Ease of Living पर जोर

बैठक के दौरान आधा दर्जन से अधिक मंत्रालयों ने अपने आगामी प्रोजेक्ट्स और सुधारों को लेकर प्रजेंटेशन दिए। इस दौरान %मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस% के सिद्धांत को दोहराते हुए पीएम ने मंत्रियों को %कम दखल और ज्यादा सहायता% की नीति अपनाने की सलाह दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को आम जनता के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि ईज ऑफ लिविंग (Ease of Living) को बढ़ावा देते हुए सही समय पर मदद और सुधार सुनिश्चित करने चाहिए।

कॉकरोच जनता पार्टी ने दिखा दिया AI कितना ताकतवर

हैलो सरकार न्यूज, नईदिल्ली। इंटरनेट पर तूफान मचाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी ने द्ध को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। महज 4 दिनों में इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ फॉलोअर्स का रिकॉर्ड बनाने वाली इस डिजिटल पार्टी ने बिना कोडिंग के, सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट की मदद से मात्र 1 घंटे में अपनी पूरी आधिकारिक वेबसाइट और एआई एंथम तैयार कर टेक जगत को हैरान कर दिया है।

AI से बनाई कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट

इंटरनेट पर इन दिनों सभी की जुबान पर एक ही नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। मुख्य न्यायाधीश के एक कथित बयान के विरोध में व्यंग के रूप में शुरू हुई इस डिजिटल पार्टी ने राजनीति ने दिखा दिया है कि द्ध कितना ताकतवर है। महज 4 दिनों में इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स बटोरकर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। संकेत उपाध्याय के यूट्यूब चैनल डबल चेक में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके के एक इंटरव्यू के अनुसार इस पार्टी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया

है।

अभिजीत दिपके के अनुसार उन्होंने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर बिना किसी कोडिंग के सिर्फ 1 घंटे में अपनी पूरी वेबसाइट और एआई एंथम तैयार कर लिया। युवाओं के इस अनूठे प्रयास और एआई की सुपरफास्ट स्पीड ने इंटरनेट पर एक नया इतिहास रच दिया है, जिसे समझना बेहद दिलचस्प है।

AI से खड़ी कर दी वेबसाइट

AI से खड़ी कर दी वेबसाइट

डबल चेक यूट्यूब चैनल पर दिए अभिजीत दीपके के इंटरव्यू के मुताबिक उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी (ष्टछ्वक्र) की पूरी वेबसाइट बनाने में द्ध का इस्तेमाल किया। दीपके के अनुसार, उनके दो दोस्तों ने वेबसाइट बनाने के लिए द्ध से मदद ली, जिससे काम बहुत आसान और तेज हो गया।

उन्होंने बताया कि AI की मदद से ग्राफिक्स बनाने के लिए उन्हें सिर्फ प्रॉम्प्ट डालना पड़ता है और वे 2 मिनट के भीतर तैयार हो जाते हैं। हैरान करने वाली बात रही कि अपनी पूरी वेबसाइट को तैयार करने में उन्हें सिर्फ एक घंटा लगा। उन्होंने बताया कि द्ध ही है जिसकी वजह से उनकी ज्यादा मेहनत नहीं लगती और चीजें काफी व्यवस्थित ढंग से हो पाती है।

वेबसाइट बनाने वाले पॉपुलर AI टूल्स

वेबसाइट बनाने वाले पॉपुलर AI टूल्स

अभिजीत दिपके की कॉकरोच जनता पार्टी इस बात का सबूत है कि आज के दौर में वेबसाइट बनाने के लिए महीनों की कोडिंग सीखने या डेवलपर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आज कई ऐस AI Website Builders और द्ध टूल्स मौजूद हैं जो सिर्फ एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के आधार पर पूरी-पूरी वेबसाइट बना देते हैं। मजे की बात है कि वेबसाइट को बनाने के लिए लिखे जाने वाले प्रॉम्प्ट्स भी AI से ही लिखवाए जा सकते हैं। Framer AI, Dora, Relume.io और 10.de1 ऐसे AI टूल्स हैं जिनकी मदद से कोई भी चंद घंटों में वेबसाइट का पूरा लेआउट, यूआई डिजाइन, एनिमेशन और रिस्पॉन्सिव पेजेस तैयार कर देते हैं।

राजस्थान में गर्मी का डबल अटैक, 22 व 23 मई को आंधी-बारिश का दौर

हैलो सरकार न्यूज

जयपुर। राजस्थान में गर्मी का सितम अभी थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 24 मई से प्रदेश में तापमान में फिर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके साथ ही कई जिलों में हीटवेव और कहीं-कहीं तीव्र हीटवेव का असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है और अगले एक सप्ताह तक बारिश की संभावना बेहद कम बताई गई है। मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में राज्य के कई इलाकों में गर्म हवाएं और हीटवेव दर्ज की गई। प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सिरोही में 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं सुबह के समय अधिकांश क्षेत्रों में हवा में नमी की मात्रा 20 से 72 प्रतिशत के बीच रही।

राज्य के उत्तरी भागों में तापमान 45 से 46 डिग्री के आसपास

मौसम विभाग का कहना है कि वर्तमान में राज्य के उत्तरी भागों में तापमान 45 से 46 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जबकि बाकी अधिकांश

क्षेत्रों में पारा 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। अगले 48 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में तेज धूलभरी हवाएं चलने की संभावना है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। हालांकि यह राहत ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी।

22 और 23 मई- 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से आंधी

पूर्वानुमान के मुताबिक 22 और 23 मई को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर-पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में दोपहर बाद मेघगर्जन और 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से आंधी चल सकती है। बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। इसके बावजूद प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा।

24 मई के बाद फिर से तेज गर्मी का दौर शुरू

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 24 मई के बाद फिर से तेज गर्मी का दौर शुरू होगा। खासकर पश्चिमी राजस्थान के जिलों में तापमान तेजी से बढ़ सकता है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर और बाड़मेर जैसे जिलों में तीव्र हीटवेव की स्थिति बनने की आशंका है। ऐसे में लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है।

राजस्थान में खेलों के लिए तैयार होगा मजबूत ईको-सिस्टम-कर्नल राठौड़

हैलो सरकार न्यूज

जयपुर। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में खेलों से जुड़े मजबूत ईको-सिस्टम के निर्माण को लेकर विस्तृत चर्चा की। राजस्थान में खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच और व्यवस्थित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने नई पहल शुरू की है। बैठक में खिलाड़ियों के ओवरऑल डवलपमेंट, आधुनिक ट्रेनिंग सिस्टम, प्रतिभाओं की पहचान, पारदर्शिता और खेल सुविधाओं के विस्तार जैसे विषयों पर विशेष फोकस किया गया। बैठक के दौरान कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि अब खेल विभाग हर महीने एक खेल को केंद्र में रखकर उसकी जरूरतों, चुनौतियों, उपलब्धियों और तकनीकी पहलुओं की गहन समीक्षा करेगा। संबंधित खेल से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकालने के साथ ही खिलाड़ियों और कोचिंग सिस्टम को भी मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले महीने दूसरे खेल पर इसी तरह फोकस किया जाएगा ताकि पूरे साल सभी खेलों को समान अवसर मिल सके। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के

नेतृत्व में है यह प्रक्रिया 12 महीने तक चलनी चाहिए, जिससे खेलों के विकास की गति निरंतर बनी रहे और प्रतिभाओं को बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके। इसके साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों की टीमों के बीच जोनल स्तर पर इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिताओं के आयोजन की योजना भी बनाई गई। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने अधिकारियों को विस्तार योजनाओं और प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का एक महीने का प्री-ट्रेनिंग कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए। कोचों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि प्रत्येक कोच अपने खिलाड़ियों की क्षमताओं, कमजोरियों और प्रदर्शन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे। बैठक में खिलाड़ियों के लिए एक व्यवस्थित और आसान सिस्टम करने पर भी चर्चा हुई। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे फॉर्मेट वाले फॉर्म तैयार किए जाएं, जिनके माध्यम से खिलाड़ी अपने खेल, चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें।

वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान राशि में वृद्धि को मंजूरी

हैलो सरकार न्यूज

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पत्रकार कल्याण, सम्मान एवं सुरक्षा के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने राज्य के पूर्णकालिक वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए सम्मान राशि को 15 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शर्मा द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (डीआईपीआर) ने राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना में संशोधन कर पूर्णकालिक वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों की सम्मान राशि में वृद्धि करते हुए इसे 18 हजार रुपये करने की अधिसूचना जारी कर दी है। डीआईपीआर द्वारा जारी राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना (संशोधन) नियम-2026 के अनुसार ऐसे पूर्णकालिक अधिस्वीकृत पत्रकार, जिन्होंने दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्र, स्वतंत्र पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाचार एजेंसी में कम से कम 20 वर्षों तक सेवायोजन कार्य किया हो (दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाचार एजेंसी के संपादक, प्रकाशक व मालिक सहित) और जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, वे प्रतिमाह 18 हजार रुपये सम्मान राशि के पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री ने बांसवाड़ा में ली जिलास्तरीय अधिकारियों की बैठक

हैलो सरकार न्यूज

बांसवाड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए भरसक प्रयास कर रही है और इसमें कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र जनों तक पहुंचाने के साथ ही पूरी संवेदनशीलता के साथ दायित्वों के निर्वहन और सुशासन के संकल्पों को साकार करने की दिशा में समर्पित भाव से जुटने का आह्वान किया है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के तीन दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने गुरुवार को बांसवाड़ा जिला कलक्ट्रेट सभागार में जिलास्तरीय अधिकारियों की बैठक में विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, अभियानों तथा नवाचारों की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति पर विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने प्रवृत्तिवार एवं क्षेत्र वार अब तक प्राप्त उपलब्धियों की जानकारी ली तथा इनके क्रियान्वयन में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए।

जल आत्मनिर्भरता के लिए करवाए जाएं स्थायी महत्त्व के कार्य

मुख्यमंत्री ने नहरों एवं तालाबों की उपयुक्त साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि नहरों में जल वितरण तथा वर्षा काल से पूर्व जिले के जलाशयों की सफाई पर गंभीरता बरतें। उन्होंने माही की एक-एक बूंद के सदुपयोग का

आह्वान करते हुए कहा कि माही का पानी व्यर्थ न जाए। सिंचाई जल के साथ पेयजल के लिए भी माकूल प्रबन्ध सुनिश्चित रहने चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान पर जोर देते हुए जल आत्मनिर्भरता को सर्वोपरि बताया और कहा कि स्थायी महत्त्व के कार्यों को गति दी जाए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ तथा समय पर पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि जन-उपयोगी संसाधनों और सेवाओं का पूरा-पूरा लाभ ग्रामीणों तक पहुंचना चाहिए।

अवैध धर्मान्तरण तथा राजनैतिक गतिविधियों में लिप्त कार्मिकों पर होगी सख्त कार्रवाई

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे फील्ड विजिट पर अधिक ध्यान देते हुए अपनी यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों की जरूरतों के प्रति सतर्क रहें और जहां कहीं कोई समस्या सामने आए, स्वत: संज्ञान लेकर इनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी ग्राम्यांचलों में भ्रमण, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य पूरी गंभीरता के साथ करें।

उन्होंने अवैध धर्मान्तरण करवाने वालों तथा राजनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए करें ठोस प्रयास

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि वर्तमान सत्र के दौरान विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने की दिशा में योजनाबद्ध रूप से पूरी तैयारी के साथ काम किया जाए ताकि बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और ठहराव सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने जिले में चन्दन वन विकसित किए जाने की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इनमें 11-11 हजार चन्दन के पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने वन विभागीय योजनाओं, वन विकास गतिविधियों, हरियालो राजस्थान आदि पर जोर देते हुए लक्ष्य के अनुरूप पौधरोपण के साथ ही वन संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हर स्तर पर प्रयास करने का आह्वान किया।

उन्होंने नशे पर रोकथाम, शहर की सड़कों की मरम्मत व पेचवर्क तत्काल सुनिश्चित करने के साथ ही शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता बनाए रखने और जल समस्या सामने आने पर तत्काल कार्यवाही करते हुए राहत देने के निर्देश दिए।

जयपुर में नीट पेपर लीक पर कांग्रेस का महाप्रदर्शन-पुलिस से तीखी धक्का-मुक्की

हैलो सरकार न्यूज

जयपुर। राजधानी जयपुर की सड़कें आज उस समय सियासी अखाड़े में तब्दील हो गईं जब नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में बीजेपी मुख्यालय की ओर उग्र कूच किया।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जबरदस्त धक्का-मुक्की देखने को मिली। बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को भारी वाटर कैनन

(पानी की बौछार) का इस्तेमाल करना पड़ा। डोटासरा को कंधों पर उठाया, विधायक बैरिकेड्स पर चढ़े कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से शुरू हुआ यह पैदल मार्च जैसे ही शहीद स्मारक पार कर बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ा, पुलिस ने भारी जाब्ते के साथ बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक लिया। इस दौरान माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया।

युवा विधायक मनीष यादव पुलिस के लगाए बैरिकेड्स पर चढ़ गए और आगे जाने की कोशिश करने लगे, जिन्हें पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। इसी बीच, जोश से भरे कार्यकर्ताओं ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को अपने कंधों पर बैठा लिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

नीट का पेपर कहां मिलेगा, बीजेपी के बाड़े में% के लगे नारे

बीजेपी ऑफिस को घेरने निकले हजारों कार्यकर्ताओं के हुजूम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तीखे तंज कसते हुए नारे लगाए कि- नीट का पेपर कहां मिलेगा, बीजेपी के बाड़े में। कांग्रेस ने सीधे तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और उनके पुतले फूंके।

धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और हृञ्ज को भंग करे सरकार- डोटासरा

प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल से लगातार नीट का पेपर लीक हो रहा है। देश की प्रतिष्ठित परीक्षा करवाने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पर से अब देश की जनता और छात्रों का विश्वास पूरी तरह उठ चुका है, इसलिए इस संस्था को तुरंत भंग कर देना चाहिए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए।

डोटासरा ने आगे कहा कि केंद्र सरकार इस महाघोटाले में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। देश के 22 लाख मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले असली गुनहगारों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने दिखावे के लिए जांच सीबीआई (CBI) को जरूर सौंपी है, लेकिन कांग्रेस मांग करती है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में ही होनी चाहिए। गौरतलब है कि इस मुद्दे को लेकर पिछले दो दिनों से पूरे राजस्थान में कांग्रेस ब्लॉक और जिला स्तर पर लगातार उग्र प्रदर्शन कर रही है।

तमिलनाडु में तमिल राजनीति के उदय से उम्मीद की नई किरणें

(लेखक- विनोद कुमार सिंह)

तमिलनाडु विधान सभा चुनाव 26 के बदलते जनादेश ने तमिल द्रविड़ राजनीति से 'नई तमिल राजनीति' भारतीय लोकतंत्र को दिया नया संदेश

वैश्विक राजनीतिक पटल पर सैदव ही भारत व भारतीय लोकतंत्र की चर्चा होती रहती है।भारत में संविधान ही सर्वोपरि है।जो अपने नागरिको मौलिक अधिकारो व कर्तव्यों की स्पष्ट उल्लेख किया है। यहाँ के नागरिकों को मताधिकार दिया है।भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत रही है कि यहाँ जनता समय-समय पर सत्ता, समीकरण और राजनीतिक विचार घारों व धारणाओं को बदलती रही है।भारतीय राजनीति में कोई भी राजनीतिक दल की शक्ति स्थायी नहीं होती।कभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का प्रभाव चरम पर होता है,तो कभी क्षेत्रीय अस्मिता नई राजनीतिक धारा बनकर उभरती है। विगत दिनों दक्षिण भारत का तमिलनाडु राज्य इसी राजनीतिक परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण रहा है।सर्वविदित रहे कि सन् 1967 में जब सी एन अन्ना दुरई के नेतृत्व में द्रविड़ राजनीति ने कांग्रेस के लंबे राजनीतिक वर्चस्व को समाप्त कर सत्ता के सिंघासन हासिल की थी,तब शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि आने वाले दशकों में तमिलनाडु भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक प्रयोगशाला बन जाएगा।उस दौर में द्रविड़ आंदोलन केवल चुनाव जीतने का माध्यम नहीं था,बल्कि सामाजिक न्याय, भाषायी अस्मिता,क्षेत्रीय स्वाभिमान और राजनीतिक आत्मसम्मान का बड़ा आंदोलन बन चुका था।तमिल समाज ने पहली बार यह महसूस किया कि दिल्ली की राजनीति से अलग उनकी अपनी भी एक राजनीतिक पहचान हो सकती है।यही वह दौर था जब राजनीति और सिनेमा ने मिलकर दक्षिण भारत में एक नई सामाजिक चेतना को जन्म दिया।तमिल फिल्मों के संवाद केवल मनोरंजन नहीं रहे,बल्कि राजनीतिक संदेश बन गए।फिल्मी के सुनहरे पर्दे पर गरीबों के रक्षक और अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले नायक जनता की वास्तविक राजनीति के नायक बनते चले गए।

इसी राजनीतिक-सांस्कृतिक वातावरण से एम जी रामा चन्द्रन जैसे करिश्माई नेता उभरे,जिन्होंने जनता के दिलों पर ऐसा प्रभाव स्थापित किया कि फिल्मों की लोकप्रियता सीधे राजनीतिक जनसमर्थन में बदल गई।उनके जे जयललिता ने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया और तमिल राजनीति में महिला नेतृत्व की एक अलग पहचान बनाई।दक्षिण भारत में फिल्म और राजनीति का यह अनूठा संगम धीरे-धीरे आंध्र प्रदेश तक पहुँचा,जहाँ एन टी रामा राव ने तेलुगु अस्मिता को राजनीतिक शक्ति में बदल दिया।यह वह नया दौर था जब राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के सामने क्षेत्रीय दलों की शक्ति तेजी से बढ़ रही थी।लगभग छह दशकों तक तमिलनाडु की राजनीति द्रविड़ दलों के इर्द-गिर्द धुमती रही।कभी डी एम के सत्ता में आई तो कभी ए आई ए डी एम के लेकिन राजनीतिक केंद्र वहीं बना रहा।जनता के सामने विकल्प बदलते रहे,किन्तु राजनीति का मूल स्वर द्रविड़ विचारधारा ही बनी रही,किन्तु समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता।राजनीति में भी पीढ़ियाँ बदलती हैं,प्राथमिकताएँ बदलती हैं और जनता की अपेक्षाएँ भी बदल जाती हैं।वर्ष 2026 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव इसी परिवर्तन का सबसे बड़ा संकेत बनकर सामने आया।इस चुनाव ने न केवल राजनीतिक पंडितों के सभी अनुमान उलट दिए,बल्कि यह भी साबित कर दिया कि जनता जब परिवर्तन का मन बना लेती है,तो दशकों पुरानी राजनीतिक संरचनाएँ भी हिल जाती हैं।तमिल फिल्म जगत के लोकप्रिय अभिनेता विजय के नेतृत्व में उभरी नई राजनीतिक धारा ने पहली बार तमिलनाडु की राजनीति को द्रविड़ बनाम द्रविड़ की पारंपरिक लड़ाई से बाहर निकालने का प्रयास किया।विजय ने स्वयं को केवल अभिनेता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया,बल्कि 'नई तमिल राजनीति' के नायक के रूप में स्थापित करने की कोशिश की।उनकी सभाओं में उमड़ती युवाओं की भीड़,सोशल मीडिया पर असाधारण लोकप्रियता और पारंपरिक राजनीति के विरुद्ध आक्रोश ने चुनावी वातावरण को पूरी तरह बदल दिया।शुरुआत में राजनीतिक विश्लेषक इसे केवल 'स्टारडम का प्रभाव' मान रहे थे,लेकिन विधान सभा चुनाव के परिणामों ने यह साबित कर दिया कि तमिलनाडु की जनता बदलाव चाहती थी।तमिलनाडु विधानसभा की कुल 234 सीटों में बहुमत के लिए 118 सीटों की आवश्यकता थी।चुनाव परिणामों में विजय की पार्टी टी वी के ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरकर सबको चौंका दिया।वहीं डी ए के 59 सीटों पर सिमट गई और ए आई ए डी एम के गठबंधन लगभग 53 सीटों तक सीमित रह गया।कांग्रेस को केवल 5 सीटों से संतोष करना पड़ा।इन परिणामों ने केवल सरकार का गणित नहीं बदला,बल्कि तमिलनाडु की राजनीति की आत्मा में चल रहे परिवर्तन को भी उजागर कर दिया।यह चुनाव भावनात्मक नारों और पारंपरिक राजनीतिक विरासत से आगे बढ़कर नई आकांक्षाओं का चुनाव बन चुका था। युवाओं की नई पीढ़ी रोजगार चाहती है,तकनीकी विकास चाहती है,उद्योग चाहती है,डिजिटल अवसर चाहती है और सबसे अधिक पारदर्शी शासन चाहती है।

पहली बार मतदान करने वाले लाखों युवा मतदाताओं ने जातीय और परंपरागत राजनीतिक निष्ठाओं से ऊपर उठकर 'नए नेतृत्व' पर भरोसा जताया।यही कारण रहा कि शहरी क्षेत्रों,आईटी कॉरिडोर और शिक्षित युवाओं वाले निर्वाचन क्षेत्रों में पारंपरिक दलों को अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पाया।राजनीतिक विश्लेषकों की सबसे बड़ी भूल यह रही कि वे तमिलनाडु की राजनीति को पुराने चुनावी गणित से समझने का प्रयास करते रहे,जबकि जनता का मन बदल चुका था।एग्जिट पोल और राजनीतिक सर्वेक्षण जहाँ द्रविड़ दलों की मजबूत वापसी का दावा कर रहे थे,वहीं मतदाताओं ने चुपचाप एक नया राजनीतिक संदेश लिख दिया।दरअसल तमिलनाडु में यह परिवर्तन अचानक नहीं आया।पिछले कुछ वर्षों से जनता के भीतर नेतृत्व को लेकर एक खालीपन महसूस किया जा रहा था।एम करुणा निधि और जयललिता जैसे बड़े नेताओं के जाने के बाद राजनीति में वह भावनात्मक करिश्मा दिखाई नहीं दे रहा था जिसने दशकों तक जनता को जोड़े रखा था।इसी राजनीतिक रिक्तता में नए चेहरे और नई राजनीति के लिए जगह बनी। विजय ने चुनाव प्रचार के दौरान बार-बार 'तमिल अस्मिता' और 'नई पीढ़ी की राजनीति' को केंद्र में रखा।उन्होंने पारंपरिक द्रविड़ राजनीति से दूरी बनाते हुए स्वयं को भविष्य की राजनीति का चेहरा साबित करने का प्रयास किया। इस चुनाव का सबसे बड़ा झटका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेश को लगा। कभी दक्षिण भारत में मजबूत राजनीतिक आधार रखने वाली कांग्रेस अब गठबंधन की राजनीति तक सीमित दिखाई दे रही है। तमिलनाडु के परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल क्षेत्रीय दलों के सहारे राजनीति करने से किसी राष्ट्रीय दल का जनाधार मजबूत नहीं हो सकता।कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट स्थानीय नेतृत्व का अभाव है।पार्टी के पास ऐसा कोई करिश्माई चेहरा नहीं दिखता जो तमिलनाडु की जनता के भीतर नई ऊर्जा पैदा कर सके।यही कारण है कि चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक पुनर्गठन और दक्षिण भारत की नई रणनीति पर गंभीर चर्चा प्रारम्भ हो गई है।राजनीतिक दृष्टि से देखें तो तमिलनाडु का यह जनादेश केवल एक राज्य की घटना नहीं है।यह भारतीय राजनीति में बदलती सामाजिक मानसिकता का संकेत है।आने वाले समय में क्षेत्रीय पहचान,युवा नेतृत्व,डिजिटल राजनीति और सांस्कृतिक स्वाभिमान का प्रभाव और अधिक बढ़ सकता है।राजनीति के विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य की राजनीति अब केवल जातीय समीकरणों और पारंपरिक वोट बैंक के सहारे नहीं चलेगी।सोशल मीडिया,युवा मतदाता और राजनीतिक पारदर्शिता नए निर्णायक कारक बन चुके हैं। तमिलनाडु ने यह संदेश पूरे देश को दे दिया है।दिलचस्प बात यह भी रही कि इस चुनाव में जनता ने 'स्थिरता बनाम परिवर्तन' के बीच परिवर्तन को प्राथमिकता दी।यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जनता जब बदलाव चाहती है,तो सबसे मजबूत राजनीतिक किले भी ढह जाते हैं।तमिलनाडु ने एक बार फिर भारतीय राजनीति को नई दिशा देने का काम किया है।कभी इसी राज्य ने कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती दी थी,फिर द्रविड़ राजनीति को राष्ट्रीय विमर्श बनाया और अब 'नई तमिल राजनीति' की चर्चा शुरू कर दी है।आज पूरा देश तमिलनाडु के राजनीतिक घटना क्रम को इसलिए ध्यान से देख रहा है क्योंकि वहाँ से उठी राजनीतिक लहर आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी बदल सकती है।

तमिलनाडु विधान सभा चुनाव 26 के बदलते जनादेश ने तमिल द्रविड़ राजनीति से 'नई तमिल राजनीति' भारतीय लोकतंत्र को दिया नया संदेश।दरअसल लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जनता जनार्दन का मौन निर्णय होता है।राजनीतिक पंडित अक्सर आँकड़ों में उलझ जाते हैं,लेकिन जनता अपने मन का फैसला चुपचाप करती है।तमिलनाडु के इस जनादेश ने एक बार फिर यही सिद्ध किया है कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के हाथ में ही होती है।विगत विधान सभा के चुनाव 26 का परिणाम केवल सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है।यह बदलती पीढ़ी,नई आकांक्षाओं,क्षेत्रीय स्वाभिमान और राजनीतिक पुनर्जागरण की कहानी भी है।भविष्य के आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति का नया अध्याय दक्षिण भारत से ही लिखा जाए।अगर यदि ऐसा होता है,तो इतिहास यह अवश्य दर्ज करेगा कि तमिलनाडु ने एक बार फिर देश को राजनीति की नई दिशा दिखाई थी।

(आलेख-विनोद कुमार सिंह 'तकियावाला'स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तम्भकार)

संपादकीय

बीमार अस्पताल

गाल बजाते राजनेता और लोक कल्याणकारी होने का दावा करती सरकारों की नाक के नीचे सरकारी अस्पतालों की कैसी बदहाली है, ये किसी से नही छिपा है। लोकलुभावन कार्यक्रमों पर पैसा पानी की तरह बहाने वाली सरकारों व मंत्रियों की प्राथमिकताओं में, वे सरकारी अस्पताल कभी नहीं रहे हैं, जो गरीबों व साधनविहीन लोगों का अंतिम आश्रय होते हैं। कायदे से तो सरकारों को इस मुद्दे को प्राथमिकता मानते हुए तत्काल प्रभाव से अस्पतालों की दशा सुधारनी चाहिए। लेकिन विडंबना है कि हर बार न्यायालय को ही जनहित से जुड़े मुद्दों पर सख्ती दिखाकर सरकारों को कार्रवाई करने को कहा जाता है। एक बार फिर पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश से पंजाब तथा हरियाणा सरकारों की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के संचालकों को एक बेहद जरूरी झटका लगा है। हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिला अस्पताल में आईसीयू सुविधाओं के साथ-साथ सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। निश्चित रूप से न्यायालय के इस तरह के सकारात्मक हस्तक्षेप से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सत्ताधीशों के वायदों और उनके क्रियान्वयन के बीच बढ़ती खाई ही उजागर होती है। वहीं अदालत की कार्यवाही के दौरान पंजाब सरकार की ओर से न्यायालय को सूचित किया गया कि राज्य के 23 जिलों में से केवल छह जिला अस्पतालों में ही एमआरआई की सुविधा उपलब्ध है। दूसरी ओर राज्य के अस्पतालों में दो हजार से अधिक जनरल मेडिकल ऑफिसरों के पद और अन्य सैकड़ों विशेषज्ञों के पद खाली पड़े हुए हैं। वहीं कई जिलों के सरकारी अस्पतालों में कार्यशील आईसीयू की कमी है। अदालत ने हरियाणा सरकार से भी गहन देखभाल व निदान सुविधाओं की कमियों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। निस्संदेह, इन खामियों से फिर उजागर हुआ है कि अनेक सरकारी अस्पतालों में महंगे चिकित्सा उपकरण अक्सर बिना इस्तेमाल के या कम उपयोग में क्यों रहते हैं। वहीं दूसरी ओर विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा भी गरीब व जरूरतमंद मरीजों की तात्कालिक जरूरतों को अनदेखा ही किया जाता है। न्यायालय की इस बात से बिल्कुल सहमत हुआ जा सकता है कि मौजूदा दौर में सीटी स्कैन,एमआरआई और आईसीयू तक मरीजों की पहुंच विलासिता नहीं, बल्कि बुनियादी स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता बन गई है। जो इस बात पर भी बल देता है कि सरकारें जिला स्तरीय क्रियाशील बुनियादी ढांचा बनाने के बजाय अनिश्चित काल तक आउटसोर्सिंग या रेफरल प्रणालियों पर निर्भर नहीं रह सकती हैं। वास्तव में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली केवल खरीद की कमी से ही नहीं, बल्कि बिना योजना के भारी-भरकम खरीद की प्रवृत्ति से भी ग्रस्त है। वहीं दूसरी ओर अकसर तकनीशियनों की अनुपलब्धता से एमआरआई मशीनें स्थापित नहीं हो पाती हैं। वहीं अनुबंध समाप्त होने के कारण अक्सर वेंटिलेटर धूल खाते रहते हैं। दूसरी तरफ रेडियोलॉजिस्ट और बायोमेडिकल इंजीनियरों की अनुपस्थिति के कारण निदान सेवाओं को आउटसोर्स किया जाता है। बार-बार की गई ऑडिट रिपोर्टों से पता चलता है कि सरकारी अस्पतालों में करोड़ों रुपये के जीवन रक्षक उपकरण महीनों से लेकर वर्षों तक बेकार ही पड़े रहते हैं। जिसका खमियाजा जरूरतमंद मरीजों को उठाना पड़ता है। किसी भी अस्पताल में एक खराब सीटी स्कैनर की वजह से दुर्घटना पीड़ितों, कैंसर के मरीजों और हृदयाघात के रोगियों के उपचार में देरी होती है।

सोशल मीडिया, जनभावनाएँ और भारत की लोकतांत्रिक सजगता

लेखाराम बिश्नोई
लेखक विचारक

डिजिटल युग में सोशल मीडिया केवल मनोरंजन या संवाद का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह जनमत निर्माण, राजनीतिक विमर्श और सामाजिक आंदोलनों का शक्तिशाली मंच बन चुका है। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में सोशल मीडिया का प्रभाव अत्यंत व्यापक है, जहाँ करोड़ों युवा प्रतिदिन विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से समाचार, विचार और राजनीतिक संदेश प्राप्त करते हैं। ऐसे समय में यह आवश्यक हो जाता है कि नागरिक किसी भी डिजिटल अभियान, संगठन या सोशल मीडिया खाते पर आँख बंद करके विश्वास न करें, बल्कि विवेकपूर्ण दृष्टि से उसकी सत्यता और उद्देश्य को समझें।

हाल के वर्षों में कई ऐसे सोशल मीडिया समूह और डिजिटल अभियान सामने आए हैं जो स्वयं को जनता की आवाज़ बताकर लोगों की भावनाओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इनमें कुछ संगठन राजनीतिक रूप से प्रेरित होते हैं, कुछ वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, जबकि कुछ केवल सोशल मीडिया की लोकप्रियता और प्रभाव का उपयोग कर जनमत को दिशा देने का प्रयास करते हैं। यह स्थिति लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है।

भारत का लोकतंत्र विचारों की विविधता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित है। संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार देता है। किंतु यह स्वतंत्रता तब चिंताजनक हो जाती है जब सोशल मीडिया का उपयोग समाज में विभाजन, वैमनस्य या भ्रामक प्रचार के लिए होने लगे। कई बार देखा गया है कि कुछ डिजिटल मंच जातिगत भावनाओं, क्षेत्रीय असंतोष या राजनीतिक आक्रोश को बढ़ावा देकर समाज को ध्रुवीकृत करने का प्रयास करते हैं। इससे सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है।

आज सोशल मीडिया पर फ्बॉट नेटवर्कफ्र और फ्पेड प्रचारफ्र जैसी प्रवृत्तियाँ भी तेजी से बढ़ रही हैं। कृत्रिम रूप से फॉलोअर्स बढ़ाना, ट्रेंड चलाना, या किसी विचार को अत्यधिक लोकप्रिय दिखाना अब एक संगठित डिजिटल उद्योग बन चुका है। कई बार ऐसे अकाउंट कुछ ही दिनों में लाखों फॉलोअर्स प्राप्त कर लेते हैं, जबकि उनकी वास्तविक जनस्वीकृति उतनी व्यापक नहीं होती। इससे आम नागरिक भ्रमित हो सकता है कि कोई विचार या अभियान वास्तव में कितना लोकप्रिय है। लोकतंत्र में जनमत का निर्माण स्वाभाविक होना चाहिए, कृत्रिम नहीं।भारतीय समाज की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सामाजिक विविधता और सांस्कृतिक एकता रही है। यदि सोशल मीडिया का उपयोग केवल राजनीतिक विरोध, संस्थाओं पर अविश्वास या जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा, तो इसका नकारात्मक प्रभाव राष्ट्र की स्थिरता पर पड़ेगा। स्वस्थ लोकतंत्र में सरकार की आलोचना आवश्यक है, परंतु आलोचना और दुष्प्रचार में अंतर समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तथ्य आधारित विमर्श लोकतंत्र को मजबूत करता है, जबकि भ्रामक प्रचार सामाजिक अविश्वास को जन्म देता है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए। नागरिकों, विशेषकर युवाओं, को यह समझना होगा कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर जानकारी सत्य नहीं होती। किसी भी पोस्ट, वीडियो या अभियान को साझा करने से पहले उसकी तथ्यात्मक जांच आवश्यक है। यह भी देखना चाहिए कि उस जानकारी का स्रोत क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और उससे किसे लाभ

मिल रहा है।

सरकार, मीडिया संस्थानों और समाज को मिलकर एक ऐसी डिजिटल संस्कृति विकसित करनी होगी जहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे, लेकिन राष्ट्रीय हित, सामाजिक सद्भाव और तथ्यात्मक सत्यता भी सुरक्षित रहे। भारत की लोकतांत्रिक परंपरा हमेशा संवाद, सहिष्णुता और विवेक पर आधारित रही है। इसलिए नागरिकों को भावनात्मक उत्तेजना के बजाय तार्किक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

अंततः, सोशल मीडिया एक शक्तिशाली साधन है। यह राष्ट्र निर्माण का माध्यम भी बन सकता है और समाज में भ्रम फैलाने का कारण भी। यह निर्भर करता है कि उसका उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय दृष्टिकोण यही कहता है कि लोकतंत्र में सजग नागरिक ही सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। इसलिए जनता को किसी भी डिजिटल अभियान या सोशल मीडिया प्रभाव से प्रभावित होने से पहले सत्य, तथ्य और राष्ट्रहित को प्राथमिकता देनी चाहिए।

लेखाराम बिश्नोई
अधिवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता

कौन बने राजा

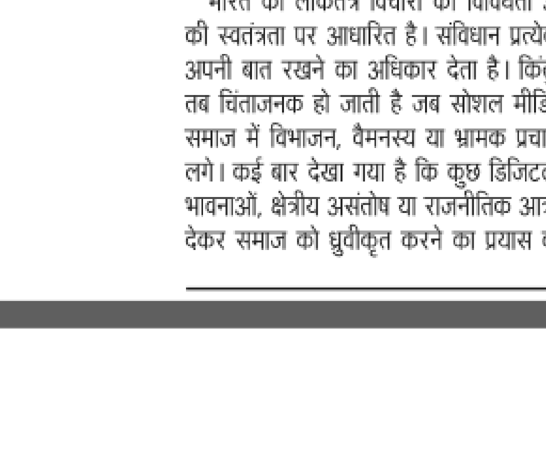

भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को पक्षियों का राजा माना गया है लेकिन वे अपने स्वामी की सेवा में इतना व्यस्त रहते थे कि उन्हें पक्षियों का हालचाल जानने का समय ही नहीं मिल पाता था। एक दिन पक्षियों ने अपनी सभा बुलाई और इस बात पर विचार-विमर्श किया कि ऐसे राजा का क्या लाभ, जो कभी हमें देखने तक नहीं आता।

सभी ने काफी सोच-विचार कर उल्लू को राजा घोषित कर दिया। उल्लू के राजतिलक की तैयारी होने लगी, तभी एक कोने में बैठे कौवे ने चिल्लाते हुए कहा कि यह फैसला हमें मंजूर नहीं है। राजा गरुड़ को भले ही हमारे पास आने का समय न मिलता हो, लेकिन जब भी मौका मिलेगा वह अवश्य आएंगे। मगर उल्लू को राजा बनाने का क्या लाभ, जिसे दिन में दिखाई ही नहीं पड़ता।

वह हमारी परेशानियों को कैसे हल करेगा। वह दूसरों की बातें सुनकर फैसला करेगा जिसका परिणाम यह होगा कि चाटुकारों का बोलबाला हो जाएगा।

किसी ने तर्प दिया कि उल्लू रात में देख सकते हैं इसलिए वह रात में हमारी समस्या सुलझा देंगे। कौवे ने कहा- ऐसा राजा मुझे मंजूर नहीं जो रात में आकर हमारी नींद हराम करे। फिर हम पक्षी रात में ठीक से देख नहीं पाते। हम पहचानेंगे कैसे कि उल्लू ही आया है।

इस बात का लाभ उठाकर कोई राक्षस उसकी जगह आ सकता है और हमें मारकर खा सकता है। पक्षियों ने मान लिया कि राजा ऐसा होना चाहिए, जिसे प्रजा के दुख-दर्द दिखाई तो पड़ें। अंत में गरुड़ को ही राजा बनाए रखने का फैसला किया गया।

विचार मंथन

कानून सबके लिए समान कहां है यह संवैधानिक सिद्धांत?

(लेखक- सनत जैन)

हाल के वर्षों में न्यायपालिका की निष्पक्षता, भ्रष्टाचार और जवाबदेही को लेकर जितने गंभीर सवाल उठ रहे हैं। संसद में सरकार ने जो जानकारी दी है, उसमें हजारों शिकायतें सरकार के पास भ्रष्टाचार की पंहुची हैं। उनमें पूर्व दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा का मामला सबसे अधिक चिंताजनक है। उनके आवास से करोड़ों रुपये के जले हुए नोट मिले, सुप्रीम कोर्ट की समिति ने जांच की, उन्हें इस्तीफा देने की सलाह दी गई, लेकिन उन्होंने पहले इस्तीफा नहीं दिया। बाद में उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया, जहां उन्हें कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपा गया। अब उन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा भेज दिया है, किंतु उसके स्वीकार न होने तक वे अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों की सूची में बने हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने भारतीय न्यायपालिका की जवाबदेही और भ्रष्टाचार की व्यवस्था पर गहरे प्रश्न खड़े कर दिए हैं। हजारों शिकायतें प्राप्त होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सरकार ने जो चुप्पी साध रखी है। कोई कार्यवाही नहीं की यह चिंता का विषय है। सबसे बड़ा सवाल यह है, यदि किसी न्यायाधीश पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हों। वह महाभियोग प्रक्रिया पूरी होने से पहले इस्तीफा दे दे, तो क्या उसके विरुद्ध आगे कोई प्रभावी कार्रवाई संभव नहीं होती है। संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का एकमात्र संवैधानिक तरीका संसद में महाभियोग ही है। यह प्रक्रिया इतनी जटिल और राजनीतिक सहमति पर आधारित है कि व्यवहार में शायद ही कभी पूरी हो पाती है। ऐसे में यदि कोई न्यायाधीश इस्तीफा दे देता है, तो महाभियोग स्वतः अप्रासंगिक हो जाता है। जब भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायत न्यायपालिका अथवा सरकार के पास जाती है। ऐसी स्थिति में आंतरिक जांच कराकर सरकार यदि राष्ट्रपति के माध्यम से उनकी सेवा समाप्त करके उनके ऊपर मुकदमा चला सकती है। सरकार नियुक्ति करती है। कदाचरण में उसके पास हटाने का अधिकार भी होता है। यह तर्क भी सामने आ रहा है कि न्यायाधीशों को मिले संवैधानिक संरक्षण का उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना था, न कि भ्रष्टाचार के आरोपों से सुरक्षा देना। न्यायाधीश संरक्षण कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों के कारण सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन और पद की गरिमा पर तत्काल प्रभाव डालना कठिन है। यही सुरक्षा जवाबदेही न्याय व्यवस्था को निष्प्रभावी बना दे, तो जनता का न्यायपालिका पर विश्वास कम या खत्म होना स्वाभाविक है। यशवंत वर्मा के मामले में अभी तक किसी आपराधिक प्राथमिकी या विस्तृत आपराधिक जांच की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई। यदि किसी सामान्य सरकारी अधिकारी के यहां इतनी मात्रा में संदिग्ध नकदी मिलती, तो प्रवर्तन एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो जातीं। न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के नाम पर यदि जांच प्रक्रिया ही ना हो, तो इससे कानून सबके लिए समान है का संवैधानिक सिद्धांत कमजोर पड़ जाता है। यह सही है, किसी भी न्यायाधीश को केवल आरोपों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। न्यायिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की मूल शर्त है। लेकिन स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन भी आवश्यक है। अब समय आ गया है कि संसद और न्यायपालिका मिलकर ऐसी व्यवस्था विकसित करें, जिसमें गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायाधीशों की स्वतंत्र, पारदर्शी और समयबद्ध जांच हो, चाहे वे पद पर हों, इस्तीफा दे चुके हों या सेवानिवृत्त हो गए हों। ट्रायल कोर्ट के जजों पर हाईकोर्ट एवं राज्य सरकार मिलकर कार्यवाही करती हैं। यशवंत वर्मा प्रकरण केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है; पिछले कुछ वर्षों में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बढ़ा है। यह समय भारतीय न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता की अग्नि परीक्षा का है। वर्तमान में जिस तरह के आरोप हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर लग रहे हैं। जिस तरह से निर्णयों को लेकर राजनैतिक दलों द्वारा खुलकर आरोप-प्रत्यारोप लगाये जा रहे हैं। भ्रष्टाचार एवं सरकार के दवाब में फैसले के आरोप लग रहे हैं। जज सेवा से स्तीफा देकर अथवा सेवा निवृत होने के तुरन्त बाद राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं। विचारधारा के अनुसार जजों की नियुक्ति के आरोप लग रहे हों। ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए जो प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें संशोधन किया जाना जरुरी है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो न्यायपालिका का अस्तित्व संकट में पड़ना तय है। हाल ही में केजरीवाल, सीबीआई और हाईकोर्ट की जज स्वर्णकांता के मामले में जो हो रहा है। न्यायपालिका में नैतिकता और मर्यादा का पालन नहीं होना चिंता का विषय है।

कच्चे तेल वायदा में जोरदार उछाल, कीमतें 9,500 के पार

हाजिर मांग और वैश्विक तेजी का असर, जून अनुबंध 106 रुपये चढ़ा

नई दिल्ली ।

मजबूत हाजिर मांग और वैश्विक तेजी के संकेतों के बीच मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स)पर कच्चे तेल के वायदा भाव में गुरुवार को जोरदार उछाल देखा गया। जून में आपूर्ति वाले कच्चे तेल का वायदा अनुबंध 106 रुपये बढ़कर 9,569 रुपये प्रति बैरल पर बंद हुआ, जिसमें कारोबारियों ने जमकर दांव लगाए। बाजार विश्लेषकों ने बताया कि प्रतिभागियों द्वारा अपनी स्थिति बढ़ाने से वायदा कारोबार में कच्चे तेल की कीमतों को समर्थन मिला। इस दौरान जून अनुबंध में कुल 4,282 लॉट का कारोबार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कच्चे तेल के दामों में तेजी दर्ज की गई। न्यूयॉर्क में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल का भाव 0.82 प्रतिशत चढ़कर 107.77 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि ब्रेंट कच्चा तेल 0.51 प्रतिशत की तेजी के साथ 105.56 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। वैश्विक बाजार में जारी यह मजबूती भारतीय वायदा बाजार में भी दिखाई दी।

इंडोनेशियाई निर्यात पर सरकारी नियंत्रण, वैश्विक कमोडिटी बाजार पर बड़ा असर

राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने सस्ता निर्यात रोकने के लिए उठाया कदम

जकार्ता ।

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने देश के प्रमुख कमोडिटी निर्यात पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण स्थापित करने का ऐलान किया है, जिससे वैश्विक कमोडिटी बाजारों में हलचल मच गई है। इस ऐतिहासिक फैसले के तहत, पाम ऑयल, कोयला और फेरोएलॉय जैसे अहम निर्यात अब केवल सरकार द्वारा चुनी गई एक कंपनी के माध्यम से ही किए जाएंगे। राष्ट्रपति प्रबोवो ने संसद में अपने भाषण में कहा कि पिछले 34 वर्षों में सस्ते दामों पर संसाधनों की बिक्री से इंडोनेशिया को लगभग 908 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, और अब देश के संसाधनों का लाभ पूरे इंडोनेशिया के लोगों को मिलना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल और थर्मल कोयला निर्यातक होने के नाते, इंडोनेशिया के इस कदम का वैश्विक कमोडिटी बाजार पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। नई व्यवस्था के तहत, शुरुआती चरण में कोयला, पाम ऑयल और फेरोएलॉय को शामिल किया जाएगा, जबकि हर तीन महीने में समीक्षा कर अन्य कमोडिटी को भी जोड़ा जा सकता है। सरकार ने निर्यातकों को तीन महीने की ट्रांजिशन अवधि दी है, जिसमें मौजूदा सौदों को पूरा किया जा सकेगा, लेकिन सरकारी एजेंसी उनकी निगरानी करेगी। बाद में सभी निर्यात संप्रभु संपत्ति कोष डनांतारा इंडोनेशिया की निगरानी में केवल सरकारी नियुक्त कंपनी के जरिए ही होंगे। इस योजना के साथ ही, सरकार ने एक और अहम नियम लागू किया है। 1 जून से, प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात करने वाली सभी कंपनियों को अपनी 100 फीसदी विदेशी कमाई इंडोनेशिया के सरकारी बैंकों में जमा करनी होगी। सरकार का दावा है कि यह कदम देश की मुद्रा रुपिया को स्थिर रखने में मदद करेगा।

अडानी पावर जयप्रकाश ग्रुप में बढ़ाएगी 24 फीसदी हिस्सेदारी

यूपी स्थित 180 मेगावॉट का चुर्क थर्मल पावर प्लांट खरीदेगी

मुंबई ।

अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेपी एसोसिएट्स) के साथ एक और बड़ी डील की है। गुरुवार को कंपनी ने बताया कि उसने जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (जेपी पावर) में 24 फीसदी हिस्सेदारी और उत्तर प्रदेश में 180 मेगावॉट का चुर्क थर्मल पावर प्लांट खरीदने के लिए डेफिनिटिव एग्रीमेंट्स किए हैं। ये समझौते जेपी एसोसिएट्स के लिए एनसीएलटी द्वारा अप्रूव्ड रेजॉल्यूशन प्लान के तहत हुए हैं। अडानी पावर ने जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (जेपी पावर) में 24 फीसदी हिस्सेदारी करीब 2993.6 करोड़ रुपये में खरीदने के लिए शेयर परचेज एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी चुर्क थर्मल पावर प्लांट और उससे जुड़ी संपत्तियों के साथ-साथ प्रयागराज पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड में जेपी एसोसिएट्स की 11.49 फीसदी हिस्सेदारी भी लगभग 1200 करोड़ रुपये में हासिल करेगी। इन डील्स का कुल मूल्य करीब 4200 करोड़ रुपये बैठता है और इन्हें कैश में पूरा किया जाएगा।

अमेरिकी उद्योग ने भारतीय सब्सिडी पर उठाए सवाल, दंडात्मक शुल्क की मांग

स्टील, फेरोएलॉय और सौर उत्पादों पर लगे आरोप; भारत ने बाजार-संचालित विकास का तर्क दिया

नई दिल्ली ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) कार्यालय की धारा 301 के तहत हुई सुनवाई ने भारत और अमेरिका के व्यापार संबंधों में नया टकराव पैदा कर दिया है।

अमेरिकी उद्योग समूहों ने भारत पर सरकारी मदद से अत्यधिक उत्पादन और बेजा सब्सिडी का आरोप लगाते हुए भारतीय सामानों पर दंडात्मक शुल्क लगाने की मांग की है। भारतीय अधिकारियों ने इसका जोरदार बचाव करते हुए कहा कि देश का विनिर्माण विस्तार बाजार-संचालित और वैश्विक व्यापार नियमों के अनुरूप है।

सुनवाई के दौरान अमेरिकी उद्योग समूहों - जिनमें स्टील, मैंगनीज फेरोएलॉय और सौर उत्पाद निर्माता शामिल हैं, ने भारत पर चीन की पुरानी चाल चलने और भारी सब्सिडी, निर्यात प्रोत्साहन व कर छूट देकर अपने उद्योगों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय उत्पादों को अमेरिका में निर्यात बढ़ाने में मदद मिली है।

अमेरिकी प्रतिनिधियों के दावों को बेबुनियाद बताते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने यूएसटीआर से कहा कि जांच अमेरिकी कानून के तहत वैधानिक सीमा को पूरा नहीं करती और इसमें किसी विशिष्ट कार्रवाई योग्य भारतीय नीति की पहचान नहीं की गई। यह जांच रद्द किए गए ट्रंप प्रशासन के जवाबी शुल्कों का संभावित विकल्प है।

बढ़ते एनपीए और घटती सेविंग ने बढ़ाई बैंकों की चिंता

नई दिल्ली ।

देश में बढ़ते कर्ज और लोगों की घटती बचत ने बैंकिंग सेक्टर की चिंता बढ़ा दी है। महंगाई और बदलती जीवनशैली के कारण लोग तेजी से लोन ले रहे हैं, जबकि बचत कम होती जा रही है। बैंकों के अनुसार पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और वाहन ऋण में लगातार वृद्धि हो रही है। दूसरी ओर सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा राशि की रफ्तार धीमी पड़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो बैंकों पर एनपीए का दबाव बढ़ सकता है। इससे वित्तीय संतुलन और बैंकिंग व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

तेल संकट के बीच जापान का व्यापार मजबूत, निर्यात में बंपर उछाल

सेमीकंडक्टर निर्यात 42 फीसदी बढ़ा, युद्ध के बावजूद उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन

तोक्यो ।

ईरान में युद्ध से तेल-गैस आपूर्ति की वैश्विक चुनौतियों के बावजूद जापान का अप्रैल व्यापार उम्मीद से कहीं अधिक मजबूत रहा। वित्त मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार निर्यात में लगातार आठवीं वृद्धि दर्ज की गई, जिससे व्यापार संतुलन घाटे से निकलकर अधिशेष में आ गया। अप्रैल में निर्यात सालाना आधार पर 14.8 प्रतिशत बढ़ा, जिसमें सेमीकंडक्टर क्षेत्र का अहम योगदान रहा, जिसका निर्यात करीब 42 प्रतिशत बढ़ा। कुल मिलाकर, जापान ने 301.9 अरब येन (1.9 अरब अमेरिकी डॉलर) का व्यापार अधिशेष दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में घाटा था। चिकित्सकीय उत्पादों, कागज और विद्युत मशीनरी के निर्यात में भी बढ़ोतरी देखी गई। चीन को निर्यात 15.5 और अमेरिका को 9.5 फीसदी बढ़ा। कुल आयात में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन मूल्य के हिसाब से जापान का तेल आयात में 50 प्रतिशत और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आयात में 20 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी आई है। ईरान युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से आपूर्ति बाधित होने से यह कमी आई है। प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने राष्ट्रीय तेल भंडार से आपूर्ति जारी करने का निर्देश दिया है। कमजोर येन और ब्रेंट क्रूड के 70 डॉलर से 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंचने के कारण जापान के लिए तेल आयात और महंगा हो गया है, जिससे नेफ्था जैसे उत्पादों का उत्पादन प्रभावित हुआ है।

इंटुइट में 3000 कर्मचारियों की छंटनीः एआई पर बढ़ते फोकस के बीच कंपनी का पुनर्गठन

वाशिंगटन।

ग्लोबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म इंटुइट (इंटुइट) ने अपने वैश्विक कार्यबल के 17 प्रतिशत कर्मचारियों, यानी करीब 3000 लोगों को नौकरी से निकालने की घोषणा की है। यह बड़ा कदम तब उठाया गया है जब कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर अपना ध्यान बढ़ा रही है और अपने संगठनात्मक ढांचे को सरल बनाने की दिशा में काम कर रही है।

कंपनी के आंतरिक मेमो के अनुसार, सीईओ ससन गुडाज़ी ने कर्मचारियों को बताया कि इस पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य जटिलता को कम करना, परिचालन को सुव्यवस्थित करना और ग्राहकों के लिए बेहतर उत्पाद व सेवाएं प्रदान करने के लिए नवाचार की गति को तेज करना है। गुडाज़ी ने बताया कि ये छंटनियां एआई द्वारा कर्मचारियों को बदलने के लिए नहीं की जा रही हैं, बल्कि यह कंपनी की कार्यक्षमता और दक्षता बढ़ाने की एक रणनीतिक पहल का हिस्सा है। इंटुइट अपने संसाधनों को एआई-आधारित प्रौद्योगिकियों की ओर स्थानांतरित कर रहा है। हाल ही में, कंपनी ने अपने क्विकबुक्स जैसे प्रमुख वित्तीय और टैक्स सॉफ्टवेयर में एआई क्षमताओं को जोड़ने के लिए ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसी अग्रणी एआई कंपनियों के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी कंपनी को अपने ग्राहकों को अधिक उन्नत और सहज समाधान प्रदान करने में मदद करेगी। कंपनी का मानना है कि एआई एकीकरण से उसके परिचालन में सुधार आएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में इस छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों को 16 सप्ताह का मूल वेतन दिया जाएगा, साथ ही कंपनी में बिताए गए प्रत्येक वर्ष की सेवा

के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का वेतन भी उनके पैकेज में शामिल होगा।

इंटुइट की इस वैश्विक छंटनी का असर भारत पर भी पड़ना तय है, खासकर बेंगलुरु में, जो कंपनी के वैश्विक हब में से एक है। यहां उत्पाद विकास, इंजीनियरिंग और डेटा साइंस की बड़ी टीमें काम करती हैं, जिसके चलते इन कार्यालयों में भी कुछ भूमिकाएं समाप्त की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, इंटुइट रेनो, नेवादा और वुडलैंड हिल्स, कैलिफोर्निया में अपने कार्यालय भी बंद कर रहा है।

यह घोषणा उसी दिन हुई जब मेटा ने अपने यहां से 8000 कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया था, जो मौजूदा टेक उद्योग में व्यापक चुनौतियों और पुनर्गठन के दौर को दर्शाता है।

भारतीय वाणिज्य दूतावास अमेरिकी बाजार में निर्यात बढ़ाने 29 मई को करेगा वेबिनार

यह सत्र भारतीय उत्पादों को वैश्विक मंच पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा

न्यूयॉर्क ।

न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाज़ार में प्रवेश दिलाने के उद्देश्य से 29 मई को एक विशेष वेबिनार का आयोजन कर रहा है। प्रमुख अमेरिकी खुदरा कंपनी वॉलमार्ट के सहयोग से आयोजित होने वाला यह सत्र भारतीय उत्पादों को वैश्विक मंच पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डिस्कवर पाथवे फॉर एक्सपोर्ट टू यूएसए फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड एमएसएमई शीर्षक वाला यह वेबिनार, भारतीय निर्यातकों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अमेरिकी खुदरा दुकानों तक अपने उत्पाद पहुंचाने के लिए आपूर्ति श्रृंखला और अन्य अनुपालन आवश्यकताओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। वॉलमार्ट के विशेषज्ञ इस दौरान निर्यात प्रक्रिया को समझने में मदद करेंगे, विशेषकर उसके 19 देशों में फैले 10,750 से अधिक स्टोरों के लिए। यह पहल सिएटल स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा पिछले महीने कॉस्टको होलसेल कॉर्पोरेशन के साथ आयोजित ऐसे ही एक सफल वेबिनार के बाद आई है, जिसमें 200 से अधिक भारतीय निर्यातकों ने भाग लिया था। ये वेबिनार भारत और अमेरिका के

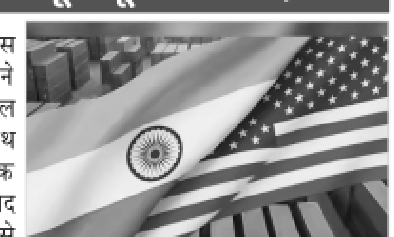

बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। पिछले महीने, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इंडिया-यूएस ट्रेड फैसिलिटेशन पोर्टल का भी अनावरण किया था, जिसका लक्ष्य 2030 तक दोनों देशों के बीच 500 अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करना और एमएसएमई व स्टार्टअप्स को समर्थन देना है।

एनवीडिया ने फिर तोड़े सारे रिकॉर्ड, मुनाफ़ा तीन गुना

एआई चिप की भारी मांग ने वॉल स्ट्रीट के अनुमानों को पछाड़ा

न्यूयॉर्क ।

कृत्रिम मेधा (एआई) चिप विनिर्माता एनवीडिया ने एक बार फिर वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों के अनुमानों को पार करते हुए प्रभावशाली तिमाही नतीजे दर्ज किए हैं। उच्च-स्तरीय एआई चिप्स की बढ़ती मांग के कारण कंपनी के राजस्व और मुनाफा में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। कंपनी ने फरवरी-अप्रैल तिमाही में 81.62 अरब अमेरिकी डॉलर का राजस्व दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 44.01 अरब डॉलर से 85 प्रतिशत अधिक है। इस दौरान उसका शुद्ध लाभ एक वर्ष पहले के 18.78 अरब डॉलर से बढ़कर 58.32 अरब डॉलर हो गया।

विश्लेषकों ने औसतन 78.91 अरब डॉलर के राजस्व और 1.75 डॉलर प्रति शेयर आय (एकमुश्त मदों को छोड़कर) का अनुमान लगाया था, लेकिन एनवीडिया ने सभी उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया। एनवीडिया ने अगली तिमाही के लिए भी 91 अरब डॉलर के रिकॉर्ड राजस्व का अनुमान लगाया है, जो विश्लेषकों के 87.29 अरब डॉलर के अनुमान से कहीं अधिक है। पिछले तीन वर्षों से कंपनी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है।

400 करोड़ के पावर प्लांट भूमि घोटाले में एसआइटी जांच शुरू

पांच सदस्यीय टीम ने चपरघटा में किया स्थलीय निरीक्षण, ग्रामीणों से भी की पूछताछ

कानपुर ।

पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित पांच सदस्यीय विशेष जांच टीम (एसआइटी) ने लगभग 400 करोड़ रुपये के बहुचर्चित पावर प्लांट भूमि घोटाले की जांच शुरू कर दी है। टीम ने पहले दिन चपरघटा स्थित विवादित स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर ग्रामीणों से पूछताछ की। अब पुलिस इस पूरे प्रकरण से जुड़े कागजात और प्रक्रिया की गहनता से पड़ताल करेगी। यह घोटाला 2011 में चपरघटा में थर्मल पावर प्लांट लगाने के बजाय, गुरुग्राम की हिमावत पावर प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनी लैंको अनपरा पावर लिमिटेड द्वारा 2332 एकड़ जमीन पर 1500 करोड़ रुपये का ऋण लेने से संबंधित है। आरोप है कि कंपनियों ने स्वयं को दिवालिया घोषित कर दिया। बैंकों ने जमीन नीलाम कर 1100 करोड़ रुपये वसूल लिए, लेकिन शेष 400 करोड़ रुपये कंपनियों ने कथित तौर पर हड़प लिए और ऋण लेकर कोई काम भी नहीं किया।

इस मामले में भोगनीपुर तहसीलदार प्रिया सिंह ने तत्कालीन एडीएम भूमि-अध्याप्ति कानपुर नगर ओके सिंह, संबंधित कंपनियों के अधिकारियों और केनरा, पंजाब नेशनल व आइडीबीआइ बैंक की गुरुग्राम स्थित शाखाओं के कर्मियों व अधिकारियों पर मूसानगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआइटी का गठन किया था। टीम ने भूमि अधिग्रहित करने वाले कुछ किसानों से भी बातचीत कर जानकारी जुटाई।

साइप्रस ने भारतीय कंपनियों को दिया यूरोप में विस्तार का न्योता

2026 तक मुंबई में व्यापार केंद्र खोलने की घोषणा

मुंबई ।

साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स ने गुरुवार को कहा कि उनका द्वीपीय देश भारतीय कंपनियों के लिए यूरोप में विस्तार करने हेतु एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में काम कर सकता है। उन्होंने सीमा-पार साझेदारियों को सुगम बनाने के लिए भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में एक व्यापार केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की। यह मुंबई व्यापार केंद्र 1 सितंबर 2026 से चालू हो जाएगा, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को प्रगाढ़ करना है। साइप्रस-भारत व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि साइप्रस यूरोपीय संघ समेत व्यापक पूर्वी भूमध्य, खाड़ी और उत्तरी अफ्रीका के बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए एक आधार प्रदान करने को तैयार है।

उन्होंने बताया कि साइप्रस यूरोपीय संघ का सदस्य होने के नाते स्थिर, पारदर्शी और ईयू-अनुरूप कारोबारी माहौल, सामान्य कानून आधारित ढांचा, अंग्रेजी भाषी वातावरण और 15 प्रतिशत की कम कॉर्पोरेट आयकर दर प्रदान करता है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडौलाइड्स ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, एआई, वित्तीय सेवाओं, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग की मजबूत संभावनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियां, विशेषकर प्रौद्योगिकी और वित्तीय नवाचार में, यूरोप में प्रवेश के लिए तेजी से साइप्रस का उपयोग कर रही हैं।

दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रत्यक्ष हवाई संपर्क स्थापित करने पर भी काम चल रहा है।

एयरटेल का प्रायोरिटी पोस्टपेड धमाका, भीड़भाड़ में भी अब मिलेगी तेज स्पीड

मौजूदा पोस्टपेड ग्राहकों को स्वतः मिलेगा लाभ, प्रीपेड यूज़र्स को करना होगा अपग्रेड

airtel PRIORIT POSTPAID

नई दिल्ली ।

दूरसंचार कंपनी एयरटेल ने अपने पोस्टपेड ग्राहकों के लिए नई प्रायोरिटी पोस्टपेड सेवा शुरू की है। यह सेवा भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी लगातार बेहतर और तेज़ स्पीड प्रदान करने का वादा करती है। एयरटेल ने ग्राहकों को भेजे पत्र में बताया कि मौजूदा पोस्टपेड ग्राहकों को इस सेवा का लाभ स्वतः मिलेगा, जबकि प्रीपेड ग्राहकों को इसका लाभ उठाने के लिए अपनी सेवा को पोस्टपेड में अपग्रेड करना होगा। भारती एयरटेल ने हाल ही में प्रायोरिटी पोस्टपेड 5जी सेवा पेश की थी, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भी अधिक विश्वसनीय दूरसंचार सेवाएं देना है। इस अनूठी सुविधा को नेटवर्क स्लाइसिंग तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। यह तकनीक पोस्टपेड ग्राहकों के लिए नेटवर्क का एक समर्पित हिस्सा आवंटित करती है, जिससे वे अन्य सेवा श्रेणियों, विशेषकर प्रीपेड ग्राहकों की बड़ी संख्या से अलग होकर एक तरह से तेज़ लेन में सेवा प्राप्त करते हैं। कंपनी के अधिकारी ने बताया कि कई ग्राहकों ने भीड़भाड़ वाले बाजारों या आयोजनों में वीडियो कॉल या डेटा अपलोड करने में कठिनाई की शिकायत की थी, जिसे हल करने के लिए एयरटेल प्रायोरिटी पोस्टपेड लाया गया है। यह खास तौर पर भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भी लगातार बेहतर अनुभव सुनिश्चित करेगा। वैश्विक दूरसंचार कंपनियों एरिक्सन और नोकिया ने एयरटेल द्वारा नेटवर्क स्लाइसिंग तकनीक के उपयोग को भारत के मोबाइल सेवा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि बताया है। नोकिया ने गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी 5जी कोर और स्लाइसिंग क्षमताएं अब भारत में भी उपलब्ध हैं, जबकि एरिक्सन ने इसे भारत के डिजिटल नेतृत्व को मजबूत करने वाला कदम बताया। इस कदम के साथ भारती एयरटेल अब अमेरिका, सिंगापुर जैसे देशों के उन अग्रणी सेवा प्रदाताओं में शामिल हो गया है जो उन्नत 5जी समाधानों के माध्यम से विशिष्ट ग्राहक अनुभव प्रदान कर रहे हैं।

खुदरा ऋण में गोल्ड लोन की चमक, सुरक्षित ऋण की ओर बढ़ रहा भारत

पर्सनल लोन को पछाड़ा, एसेट क्वालिटी में भी आया सुधार

नई दिल्ली ।

वित्त वर्ष 2026 में भारतीय खुदरा ऋण बाजार में एक निर्णायक बदलाव देखा गया है, जहां सुरक्षित ऋणों की ओर रुझान बढ़ा है। गोल्ड लोन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे तेजी से बढ़ते खंड के रूप में अपनी पहचान बनाई है। यह होम लोन के बाद दूसरा सबसे बड़ा खुदरा ऋण वर्ग बन गया है, जिसने पर्सनल लोन को पीछे छोड़ा है। बाजार में गोल्ड लोन का बढ़ता दबदबा- कुल खपत ऋण 15.3 प्रतिशत बढ़कर 118.6 लाख करोड़ रुपये हुआ, जिसे गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ने समर्थन दिया। गोल्ड लोन का प्रदर्शन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा, जिसमें सालाना आधार पर 50.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 18.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। होम और वाहन ऋण की वृद्धि स्थिर रही, जबकि सोने की बढ़ती कीमतों के कारण गोल्ड लोन का औसत आकार वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में 52 प्रतिशत बढ़कर 2.19 लाख रुपये हो गया। इस असाधारण वृद्धि को नियामक ढील और बढ़ती सोने की कीमतों से बल मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2.5 लाख रुपये तक के गोल्ड लोन के लिए लोन-टू-वैल्यू सीमा को 85 प्रतिशत तक बढ़ाने के फैसले ने नए उधारकर्ताओं को आकर्षित किया। तेज विस्तार के बावजूद, गोल्ड लोन की संपत्ति

गुणवत्ता में सुधार हुआ है। मार्च 2026 में 31 से 180 दिन का पास्ट ड्यू रेशियो घटकर 1.2 प्रतिशत रह गया, जो एक साल पहले 2 प्रतिशत था। गिरवी संपत्ति की वसूली और सोने की कीमतों में तेजी से इसमें सुधार हुआ।

गोहत्या के खिलाफ आंदोलन चला रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने किया ऐलान

शंकराचार्य गो-एलएक्स पर गाय खरीदेंगे और बेचेंगे

वाराणसी (एजेंसी)। गोहत्या के खिलाफ आंदोलन चला रहे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अब गायों की ऑनलाइन खरीद-फरोख्त का ऐलान किया है। शंकराचार्य ने गो-एलएक्स नाम से एक वेबसाइट शुरू करने का फैसला किया है, जिसके माध्यम से गायों की खरीद की जाएगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हम एक वेबसाइट बनवा रहे हैं। इस वेबसाइट के जरिए हम गायों को खरीदेंगे। जो पशुपालक या व्यापारी अपनी गाय बेचना चाहता है, वह वेबसाइट पर विज्ञापन दे सकता है। अगर कोई हिंदू अपनी गाय बेचना चाहता है, तो मुझे बेचे। हम खरीदने के लिए तैयार हैं। हम गायों को कटने नहीं देंगे और किसी गोहत्यारे को गाय खरीदने नहीं देंगे।

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गुरुवार को एक वीडियो जारी किया। वीडियो में उन्होंने कहा कि हम गायों को खरीदकर उनकी सेवा करेंगे। हिंदुओं के कहने पर ही अपने वेबसाइट बनाई है। हमने इसका नाम गो-एलएक्स रखा है। लोग अपनी गाय यहां बेच सकते हैं। गो संरक्षण को समर्पित लोग भी उन गायों को खरीदकर सेवा कर सकेंगे। गायों को ऑनलाइन खरीदने का फैसला लेने की वजह बताते हुए शंकराचार्य ने कहा कि सोशल मीडिया और कुछ समाचार माध्यमों से यह नैरेटिव फैलाया जा रहा कि यदि मुसलमान गाय खरीदना बंद कर देंगे या गो मांस खाना छोड़ देंगे तो हिंदू पशुपालक आर्थिक संकट में आ जाएंगे।

गो-एलएक्स का मकसद, गायों को कटने से बचाना है

शंकराचार्य ने कहा कि गो-एलएक्स मंच का उद्देश्य किसी भी परिस्थिति में गाय को कत्लखाने जाने से रोकना है। यह मंच ओएलएक्स की तर्ज पर कार्य करेगा। जहां गाय बेचने की इच्छा रखने वाले लोग संपर्क कर सकेंगे। गो सेवक और गो भक्त गायों को संरक्षण के लिए खरीद सकेंगे। उन्होंने कहा कि वह ऐसी गायों को खरीदेंगे जो दूध देना बंद कर दी हैं या जिनको कसाई को बेचा जा रहा। पशुपालक उन गायों को हमारी वेबसाइट पर सीधे बेच सकेंगे और हम उसकी खरीदी करेंगे।कोई भी सच्चा हिंदू अपनी गाय को कटने के लिए नहीं बेच सकता। यदि किसी व्यक्ति में वास्तविक हिंदुत्व है, तो वह कभी भी गाय को कसाई के हाथों में नहीं सौंपेगा।

मुस्लिम समाज भी गोहत्या बंदी के समर्थन में...

शंकराचार्य ने कहा कि भारत में गो हत्या बंदी के समर्थन में मुस्लिम समाज भी है। मुस्लिम समाज के काफी लोग साथ हैं। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि इस्लाम में गो मांस खाना कोई अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य नहीं है। हम ऐसे लोगों का स्वागत करते हैं। यदि देश में गोहत्या और गोमांस भक्षण बंद होता है, तो इससे सामाजिक सौहार्द और आपसी सद्भाव को बल मिलेगा।

इबोला वायरस को लेकर भारत सरकार ने किया अलर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अफ्रीका में फैले इबोला वायरस को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में फैले इबोला को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किए जाने के बाद भारत सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डीजीएचएस ने सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को एडवाइजरी भेजी है खासकर उन यात्रियों के लिए जो डीआर कांगो, युगांडा और साउथ सूडान जैसे हाई रिस्क देशों से आ रहे हैं। एडवाइजरी में कहा है कि अगर किसी यात्री में बुखार, सिरदर्द, कमजोरी, उल्टी-दस्त, गले में खराश या खून बहने जैसे लक्षण हैं तो उसे इमिग्रेशन से पहले ही एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर को रिपोर्ट करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि भारत में फिलहाल इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है और देश के लिए वर्तमान खतरा बेहद कम है। हालांकि सावधानी के तौर पर निगरानी और तैयारियों को और मजबूत किया जा रहा है। एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित मरीज के खून या बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आया है तो उस पर भी नजर रखी जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि भारत आने के बाद 21 दिनों के अंदर अगर लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताएं। बता दें एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गनाइजेशन इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है। इबोला एक बेहद खतरनाक बीमारी है इसलिए केंद्र सरकार ने यात्रियों से हेल्थ स्क्रीनिंग में पूरा सहयोग करने की अपील की है।

एअर इंडिया की फ्लाइट रनवे से टकराई

बंगलूरू (एजेंसी)। बंगलूरू हवाई अड्डे पर उतरते समय गुरूवार को एअर इंडिया के एक विमान में टेलस्ट्राइक की घटना हुई। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली से आ रहा विमान सुरक्षित रूप से उतर गया और चालक दल और यात्री सामान्य रूप से विमान से उतर गए। दरअसल, टेकऑफ या लैंडिंग के दौरान जब विमान का पिछला हिस्सा रनवे के संपर्क में आता है, तब टेलस्ट्राइक की घटना होती है। टेलस्ट्राइक के बाद सभी विमानों की संरचनात्मक समस्याओं के लिए जांच की जाती है। फ्लाइट में 181 यात्री सवार थे। घटना में किसी यात्री या क्रू सदस्य के घायल होने की सूचना नहीं है। सूत्रों के अनुसार, लैंडिंग से ठीक पहले विमान 'वेक टर्बुलेंस' की चपेट में आ गया। इसके बाद पायलट ने नियमों के तहत 'गो-अराउंड' करने का फैसला लिया। पायलट ने लैंडिंग टाल दी और फ्लाइट वापस हवा में ले ली। इसी दौरान उसका पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया।

नीट लीक मामला : कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन : शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान के जयपुर में गुरुवार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई, जिसमें पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलना पड़ा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय से पैदल मार्च करते हुए शहीद स्मारक पहुंचे, जहां से वे बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान शहीद स्मारक पर कार्यकर्ताओं ने डोटासरा को कंधे पर उठा लिया। वहीं, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पुलिस कमिश्नरेट के सामने सड़क पर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने विधायक मुकेश भाकर और पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को धक्का देकर आगे बढ़ने से रोका, जबकि विधायक मनीष यादव को बैरिकेड्स पर चढ़ने का प्रयास करते हुए नीचे उतारा गया। डोटासरा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला कर उनके तत्काल इस्तीफे की मांग की। उन्होंने प्रधान को चोर और धोखेबाज करार देकर कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) पर लोगों का विश्वास नहीं रहा है और एनटीए को भंग कर देना चाहिए। डोटासरा ने केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाकर कहा कि 22 लाख छात्रों के भविष्य को देखते हुए नीट पेपर लीक मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई से कराई जानी चाहिए, ताकि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो सके।

अमृतसर में घर में भीषण धमाका, दो महिलाएं झुलसीं

अमृतसर (एजेंसी)। पंजाब के अमृतसर के अनगढ़ इलाके में गुरुवार सुबह एक घर में हुए जोरदार धमाके से पूरा इलाका दहल गया। घटना के कारण घर में भीषण आग लग गई और चारों ओर अफरा-तफरी मच गई। हादसे में दो महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। अधिकारियों के मुताबिक, एक महिला की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और दूसरी भी बुरी तरह घायल है। आशंका है कि एक महिला की मौत हो सकती है, हालांकि इसकी पुष्टि अस्पताल की रिपोर्ट के बाद होगी। बात दें कि धमाका इतना तेज था कि घर की छत में गहरी दरारें पड़ गईं और बाहर लगे शीशे भी टूटकर बिखर गए। आग बहुत तेजी से फैली, जिससे घर को भारी नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड को सुबह करीब 11:45 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत गाड़ियां मौके के लिए रवाना की गईं। टीम जब पहुंची, तब स्थानीय लोग आग बुझाने में मदद कर रहे थे। फायर ब्रिगेड की टीमों ने लगभग 20 से 25 मिनट में आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग आग लगने के कारणों को लेकर तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं। कुछ लोगों ने पटाखों या अन्य ज्वलनशील पदार्थों से धमाके जैसी आवाज सुनने का दावा किया है। हालांकि, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और सभी कोणों से मामले की गहन जांच की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तक आग लगने का कोई अंतिम कारण सामने नहीं आया है और विस्तृत जांच के बाद ही सच्चाई का पता चलेगा। पुलिस मौके से सबूत जुटाकर उचित कानूनी कार्रवाई करेगी।

राजनीतिक फैसले और बीजेपी में जाने को लेकर की जा रही आलोचना

-हाईकोर्ट ने राघव की याचिका पर कहा-यह प्राइवेसी उल्लंघन का मामला नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस सुब्रह्मण्यम प्रसाद की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि राघव चड्ढा के व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन का मामला नहीं बनता। उनकी आलोचना उनके राजनीतिक फैसले को लेकर और बीजेपी में जाने को लेकर की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने राघव चड्ढा की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उनके खिलाफ अपमानजनक सामग्री हटाने की मांग की गई थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्तित्व अधिकारों का कमर्शियल इस्तेमाल और आलोचना करने में अंतर है। हाईकोर्ट ने राघव चड्ढा से कहा कि आपके राजनीतिक फैसले और बीजेपी में जाने की आलोचना हो रही है। प्रथम दृष्टया इसमें व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन का मामला नहीं बनता। कोर्ट ने कहा निस्संदेह आज़ादी के समय से ही हम आरके लक्ष्मण के कार्टून देखते आए हैं। उस दौर में शायद सोशल मीडिया इतना प्रभावशाली नहीं था, जितना आज है। बता दें राघव चड्ढा की याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित एआई-जनरेटेड डीपफेक, छेड़छाड़ वाले वीडियो, फैब्रिकेटेड भाषण और भ्रामक सामग्री को हटाने की मांग की गई है। कोर्ट ने राघव चड्ढा से कहा है कि ऐसे मामलों में मानहानि का केस दर्ज किया जा सकता है। पार्टी बदलना एक सार्वजनिक फैसला है, व्यक्तिगत नहीं। कोर्ट ने एआई से बने वीडियो पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर इन वीडियो पर आपत्ति है, तो विशेष याचिका दाखिल करें। व्यापक रूप से रोक लगाने की मांग नहीं की जा सकती।

उत्तर भारत में सूरज उगल रहा आग, यूपी के बांदा में पारा 48 पर पहुंचा

-भारत के बड़े हिस्से में 40 से 47 के बीच तापमान बना रहने की संभावना

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के उत्तर भारत में भीषण गर्मी जारी है। उत्तर भारत आग की भट्ठी में तब्दील हो गया है। कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री से पार है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। लू की तेज हवाएं तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को देश के करीब 50फीसदी हिस्से में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, विदर्भ और ओडिशा जैसे राज्यों में भारी गर्मी पड़ रही है। यूपी के बांदा में सबसे ज्यादा तापमान 48.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है।

वहीं सबसे ज्यादा गर्मी यूपी, मध्य प्रदेश और विदर्भ (महाराष्ट्र) के इलाकों में पड़ रही है। बांदा, खजुराहो, वर्धा, रोहतक और नागपुर जैसे शहर इस समय सूरज की तपिश में जल रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मई के अंत तक गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं। उत्तर-पश्चिम भारत, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत और उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में 40 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान बना रहने की संभावना है। लू की स्थिति भी जारी रहेगी। इस भीषण गर्मी में दिन के समय बाहर निकलना मुश्किल है। खेतों में काम करने वाले किसान, मजदूर और सड़क पर काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने, खूब पानी पीने, ओआरएस लेने और हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनने की सलाह दी है। सरकार और प्रशासन भी हाई अलर्ट पर हैं। स्कूलों के समय में बदलाव, पशुओं के लिए छाया और पानी की व्यवस्था जैसी तैयारियां की जा रही हैं। उत्तर भारत इस समय वाकई आग की भट्ठी बना है। अगले कुछ दिनों में अगर कोई ठंडी हवा या प्री-मानसून की बारिश नहीं हुई तो स्थिति और बिगड़ सकती है।

गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर तीखा पलटवार: कांग्रेस अब माओवादी, मुस्लिम पार्टी

खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं और जमानत पर बाहर

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। राहुल गांधी पर तीखा पलटवार कर उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब वह पार्टी नहीं रही, बल्कि एक माओवादी, मुस्लिम कांग्रेस में बदल गई है। यह बयान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले दिया।

केंद्रीय मंत्री सिंह ने स्पष्ट किया कि मंत्रिपरिषद की यह बैठक पहले से ही तय थी और इस राहुल गांधी के बयानों के जवाब में नहीं बुलाया गया था, क्योंकि मंत्रिपरिषद की बैठकें नियमित रूप से होती रहती हैं। कांग्रेस नेता पर सीधा हमला कर केंद्रीय मंत्री सिंह ने दावा किया कि देश में राहुल गांधी की पकड़ कमजोर हो गई है और कांग्रेस का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर प्रधानमंत्री मोदी को बार-बार अपशब्द कहने का आरोप लगाया, लेकिन कहा कि इन तमाम गालियों के बावजूद देश की जनता आज भी प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करती है। राहुल गांधी पर व्यक्तिगत रूप से निशाना साधकर केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि वे खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं और जमानत पर बाहर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए जिस भाषा का राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया है, वह किसी विपक्ष के नेता के लिए कतई उपयुक्त नहीं है।

केंद्रीय मंत्री सिंह ने राष्ट्रीय संकटों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व का बचाव किया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हर संकट में देश के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं और आगे भी ऐसा ही होगा। गिरिराज सिंह की यह तीखी प्रतिक्रिया राहुल गांधी द्वारा एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने के बाद आई है। राहुल गांधी ने चेतावनी दी थी कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास की अशांति के कारण भारत पर आर्थिक तूफान आने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री देश को इसतरह के संकट के लिए तैयार करने में विफल रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ हुई मुलाकात पर कटाक्ष कर कहा था कि प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ टॉफियां खा रहे थे और वीडियो बना रहे थे, जबकि देश पर संकट मंडरा रहा था।

अमरनाथ यात्रा : 3.6 लाख से अधिक पंजीकरण, दुर्गम रास्तों पर तैयारियां तेज

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। अब तक 3.6 लाख से अधिक भक्त अपना पंजीकरण करा चुके हैं, और प्रशासनिक अधिकारियों को उम्मीद है कि यह संख्या 5 लाख के आंकड़े को छू सकती है। 57 दिवसीय यात्रा 3 जुलाई को शुरू होकर 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। इस यात्रा के दोनों मार्गों बालटाल-सोनमर्ग और नुनवान-पहलगाम पर अभी भी कई स्थानों पर 10 से 12 फीट तक बर्फ जमी हुई है। हालांकि, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) इन दुर्गम रास्तों को बहाल करने में तेजी से जुटा है। बीआरओ के अधिकारियों का दावा है कि 15 जून तक दोनों मार्ग यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार कर दिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू हुए थे और अब पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू-कश्मीर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक की निर्धारित शाखाओं के माध्यम से व्यक्तिगत या छोटे समूहों के लिए जारी हैं, जबकि 5 से 30 लोगों के समूह के लिए पंजीकरण बुधवार को बंद हो गए। इस साल श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। बेस कैंप में पारंपरिक टेंट की जगह अब प्री-फैब्रिकेटेड और फाइबर स्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं।

सांसद सायोनी घोष का सिर कलम करने पर एक करोड़ का रखा ईनाम

- बाद में धमकाने वाले भाजपा नेता ने खेद जताया

सिकंदराबाद (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल से टीएमसी सांसद सायोनी घोष का सिर कलम करने वाले को एक करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा करने वाले उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता और सिकंदराबाद नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. प्रदीप दीक्षित अब अपने बयान से बैकफुट पर आ गए हैं। सोशल मीडिया पर विवादित वीडियो वायरल होने और चौतरफा घिरने के बाद उन्होंने बुधवार शाम एक नया वीडियो जारी कर अपने बयान पर खेद व्यक्त किया है।

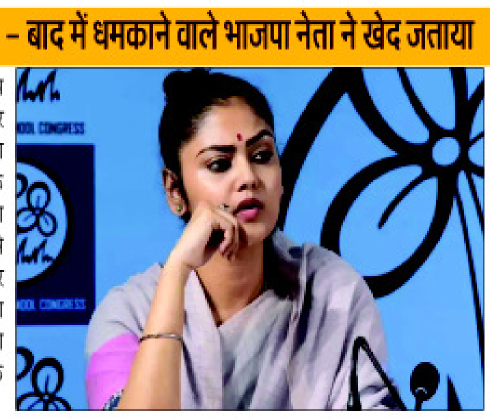

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब बुलंदशहर के सिकंदराबाद में करीब पांच दिन पहले आयोजित एक धर्म ध्वज यात्रा के दौरान डॉ. प्रदीप दीक्षित ने यह भड़काऊ बयान दिया था। वीडियो सामने आने के बाद राजनीति गर्मा गई। टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने इसे एक महिला जनप्रतिनिधि को दी गई खुली धमकी करार दिया। सायोनी घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी को टैग करते हुए स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल और कोलकाता पुलिस से इस मामले में तत्काल कड़ी कार्रवाई की अपील करते हुए कहा कि वह ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं हैं और लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाती रहेंगी। दरअसल, यह पूरा विवाद साल 2015 की एक पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट (शिवलिंग पर कथित कार्टून) से जुड़ा है। सायोनी घोष ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि वह पोस्ट उन्होंने नहीं की थी और उस समय वह महज 22 वर्ष की थीं। वह इस विषय पर पहले ही सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुकी हैं और सभी धर्मों का सम्मान करती हैं।

भाजपा नेता ने दी सफाई

सांसद सायोनी घोष के कड़े रुख और पुलिस कार्रवाई की मांग के बाद भाजपा नेता डॉ. प्रदीप दीक्षित ने बैकफुट पर आते हुए बुधवार शाम एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि सायोनी घोष उस पुरानी विवादित तस्वीर को लेकर पहले ही खेद जता चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वह किसी भी तरह की हिंसा के समर्थक नहीं हैं। उन्होंने अपने बयान पर खेद जताते हुए लोगों से अपील की कि न तो किसी को हिंसा की बात करने का अधिकार है और न ही किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का।

बंगाल के मदरसों में गाना पड़ेगा वंदे मातरम

-शुभेंदु सरकार ने जारी किए आदेश

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के सभी मदरसों में 'वंदे मातरम्'गाना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में मदरसा शिक्षा निदेशालय की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। जारी किए गए आधिकारिक आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि पहले के सभी निर्देशों और प्रथाओं को निरस्त करते हुए अब राज्य के मदरसों में दैनिक कक्षाएं शुरू होने से पहले होने वाली सुबह की प्रार्थना में 'वंदे मातरम्'गाना बेहद जरूरी होगा।

यह नया नियम राज्य के सभी सरकारी मॉडल मदरसों (इंग्लिश मीडियम), मान्यता प्राप्त सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, अप्रूव्ड एमएसके, अप्रूव्ड एसएसके और मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त मदरसों पर समान रूप से लागू होगा। सरकार ने निर्देश दिया है कि इस आदेश को तत्काल प्रभाव से पूरे राज्य में सख्ती से लागू किया जाए। मदरसा शिक्षा निदेशक की तरफ से इस आदेश की प्रतिलिपि सभी जिलाधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों, पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन और अन्य संबंधित विभागों को अनुपालन के लिए भेज दी गई है। आदेश में बताया गया है कि इसे सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद ही जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर का दर्जा देने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अधिकारियों के मुताबिक, इस फैसले का मुख्य उद्देश्य वंदे मातरम् को भी उसी कानूनी दायरे में लाना है, जिसके तहत अभी राष्ट्रगान को सुरक्षा और सम्मान मिला हुआ है। इस नए प्रस्तावित संशोधन के लागू होने के बाद, देश में वंदे मातरम गाए जाने के दौरान किसी भी तरह का अपमान करना या उसमें बाधा डालना एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। मौजूदा कानूनी नियमों के तहत, यदि कोई व्यक्ति जान-बूझकर राष्ट्रगान गाने से रोकता है या उसमें किसी प्रकार का व्यवधान पैदा करता है, तो उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। वहीं, बार-बार इस अपराध को दोहराने वालों के लिए कम से कम एक साल की अनिवार्य जेल का प्रावधान है। अब यही कड़े कानूनी प्रावधान और सजा वंदे मातरम् के अपमान पर भी लागू होंगे।

ट्रेनों में हो रही लगातार आग की घटनाएं किसी साजिश का हिस्सा हैं?

-रेलवे ने किया खुलासा, असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर किया इशारा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय रेलवे ने हाल के दिनों में ट्रेनों में अचानक आग लगने की घटनाओं को लेकर खुलासा किया है। रेलवे ने बुधवार को इन हादसों को महज इत्तेफाक या तकनीकी खराबी मानने के बजाय, इसके पीछे साजिश की आशंका जताई है। आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया गया है कि अब तक हुई जांच के नतीजे असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर साफ इशारा कर रहे हैं। इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों और रेलवे में हड़कंप मच गया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे प्रशासन ने खासतौर पर चार अलग-अलग जगहों पर हुई घटनाओं का जिक्र किया है, जिन्होंने सुरक्षा तंत्र की नींद उड़ा दी है। इनमें राजस्थान के अमरपुरा और कोटा में सामने आई घटनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, बिहार के सासाराम और पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी ट्रेनों में भड़की आग ने इस शक को और पुख्ता कर दिया है कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। रेलवे का कहना है कि इन सभी घटनाओं को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरपुरा में जहां ट्रेन के बेडरोल में आग लगाने की कोशिश की गई, वहीं हावड़ा की घटना में तो कोच के बाथरूम से पेट्रोल से सना हुआ एक कपड़ा बरामद हुआ है, जिसने साजिश के शक को और पुख्ता कर दिया है। इसी तरह कोटा में राजधानी एक्सप्रेस के बाथरूम से लपटें उठती देखी गईं। वहीं, बिहार के सासाराम स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 6 पर खड़ी सासाराम-पटना पैसेंजर ट्रेन के एक खाली कोच में किसी अज्ञात शख्स ने कोई जलती हुई चीज फेंक दी। हालांकि, शुरुआती जांच में सासाराम की घटना के पीछे शॉर्ट सर्किट का अंदेशा जताया गया था, लेकिन अब इसमें भी तोड़फोड़ का एंगल सामने आ रहा है। लगातार हो रही इन घटनाओं के बाद रेलवे प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। मामलों की तह तक जाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आरपीएफ की स्पेशल टीमें हर मामले की हर एंगल से बारीकी से जांच कर रही हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि देश की जीवनरेखा माने जाने वाले रेलवे नेटवर्क को निशाना बनाने के पीछे किन लोगों का हाथ है। इन घटनाओं के मद्देनजर रेलवे ने यात्रियों से भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की है। रेलवे ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वे अलर्ट और सुरक्षित रहें। अगर आपको ट्रेन या स्टेशन पर कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो बिना कोई देर किए तुरंत रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सूचना दें।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक कजोड़मल मीना के लिए स्काईटक प्रिन्टर्स, 111, नवाब कल्लन का बाग, एमएलए क्वार्टर, नीयर समाचार जगत, एमआई रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 303, भव्य टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर से प्रकाशित।
(इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी) समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा। RNI No. RAJHIN/2001/05699 मो. नं. 9928078717